औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्वदेशी स्टार्टअप की सशक्त मिसाल शिखा अग्रवाल

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 38 | मूल्य 05 रुपये | 08-14 फरवरी, 2026

उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती उत्तराखंड की जनजातीय महिलाएँ

खून से लथपथ हुआ देहरादून का 'हृदय'

पहाड़ों के बीच नया मार्ग
बदलेगी देहरादून-मसूरी की दूरी

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri Aviation & Tourism

SINCE 2018

A Unit of दिव्य हिमगिरि

5N/6D TOUR

Chardham

YATRA BY HELICOPTOR

ADVANCE BOOKING STARTS

BOOK NOW

POSSIBLE OPENING DATES

Yamnotri	19 April, 2026
Gangotri	19 April, 2026
Kedarnath	22 April, 2026
Badrinath	23 April, 2026

Contact for Reservation **8433456398, 9410353164**

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opp. Oxford School of Excellence, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

वर्ष 15 | अंक 38

दिव्य हिमगिरि

08-14 फरवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा आईशा प्रिंटिंग प्रेस, 292/1, चुक्खूवाला, ओंकार रोड, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

ऑनलाइन गेमिंग की लत से उभरे सवाल

ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया कितनी भयावह एवं घातक हो सकती है, इसकी एक ही दिन में दो अलग-अलग जगह घटी घटनाओं ने न केवल झकझोरा है, बल्कि यह हमारे समय, हमारी सामाजिक संरचना और हमारी सामूहिक असावधानी पर लगा हुआ एक गहरा प्रश्नचिह्न बना है। धीरे-धीरे किशोरवय को अपने चपेट में लेने वाली यह प्रवृत्ति कितनी हृदयविदारक हो सकती है, उसका उदाहरण बुधवार को घटी ये दो भयावह घटनाएं हैं। एक हृदयविदारक घटना में गाजियाबाद की तीन अल्पवयस्क बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12, 14 और 16 साल की तीन सुकोमल बहनें असमय काल-कवलित हो गई। ऑनलाइन कोरियन गेम की दीवानी बहनें कोरिया में जाकर बसने और वहीं नया जीवन शुरू करने का सपना देखती थीं। घर वालों ने जब उनकी ऑनलाइन सनक से परेशान होकर उनसे मोबाइल छीन लिए, तो वे तनाव व अवसाद में घिर गई। फिर तीनों बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी घटी जहां एक पंद्रह वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेम के अपने एक विदेशी साथी के बिछुड़ने के गम में घर में आत्महत्या कर ली। किशोर दसवीं का छात्र था। इन घटनाओं ने समाज को स्तब्ध ही नहीं किया, बल्कि भीतर तक गहरा घाव दिया है। यह कोई आकस्मिक या अलग-थलग घटना नहीं है। इससे पहले झाबुआ, भोपाल और देश के अन्य हिस्सों में सामने आई ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आभासी दुनिया किस तरह वास्तविक जीवन पर हावी होती जा रही है और हम अनजाने में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां संवेदनाएं, संवाद और जीवन-मूल्य स्क्रीन के पीछे दम तोड़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में अपराध नहीं है, न ही तकनीक शत्रु है, लेकिन जब यह बच्चों और किशोरों के लिए लत बन जाए, तो यह एक धीमा जहर बन जाती है। यह जहर चुपचाप बच्चों के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उनकी सोच, उनकी भावनात्मक संरचना और उनके निर्णय लेने की क्षमता को विकृत करता है। गेमिंग की दुनिया बच्चों को तात्कालिक रोमांच, आभासी जीत और काल्पनिक पहचान देती है, लेकिन धीरे-धीरे वही दुनिया उन्हें वास्तविक जीवन से काट देती है। परिवार, मित्र, पढ़ाई, प्रकृति, खेल और संवाद-सब कुछ पीछे छूटने लगता है। गाजियाबाद की तीनों बहनों का यह कदम इसी कटाव का चरम और भयावह परिणाम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के मस्तिष्क में आवेग नियंत्रण को कमजोर करती है। जोखिम का आकलन करने की क्षमता घटती है और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। हार, असफलता या गेम से वंचित किए जाने की स्थिति में अवसाद, क्रोध और निराशा गहराने लगती है। कई बार बच्चे आत्महत्या जैसे चरम कदम को भी एक 'गेम ओवर' की तरह देखने लगते हैं। सवाल है कि ऐसे आनलाइन खेलों की अनुमति कैसे दे दी जाती है, जो किसी बच्चे के जीवन को खतरे में डाल दे या फिर उसकी मौत का कारण बन जाए? जाहिर है, इसके पीछे कानून में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव हो सकता है मगर अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के जोखिम को हल्के में न लें और बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान उन पर नियमित नजर रखें।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

यूजीसी रेगुलेशन का शोर और जीरो परसेंटाइल वाले पीजी डॉक्टर!

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
University Grant Commission

डॉ. सुशील उपाध्याय

यूजीसी के समता रेगुलेशन के शोर में नीट पीजी की कट ऑफ जीरो और कुछ मामलों में माइनस अंकों तक निर्धारित करने जैसा गंभीर विषय गौण हो गया। देश के मेडिकल कॉलेजों में हजारों सीटें खाली रहने को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड ने नीट पीजी 2025 के परसेंटाइल में इतना चमत्कारिक बदलाव किया कि ऐसे युवा भी अब मेडिकल की पीजी डिग्री करने के पात्र हो गए, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा में जीरो प्रतिशत अथवा इससे भी कम अंक प्राप्त किए हैं। मीडिया में जिस तेजी के साथ जीरो परसेंटाइल का मामला सामने आया, उससे लग रहा था कि सरकार के स्तर पर कोई ऐसा निर्णय जरूर लिया जाएगा, जिससे देश में यह मैसेज न जाए कि अयोग्य डॉक्टरों को भी पीजी डिग्री में प्रवेश दे दिया गया। लेकिन इसी बीच यूजीसी के इक्वैलिटी रेगुलेशन, जिसके द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समता संवर्धन केंद्र स्थापित किए जाने थे, के तीखे विरोध से उपजे शोर-शराबे में जीरो अथवा माइनस परसेंटाइल के आधार पर मेडिकल डिग्री में प्रवेश की बात कहीं नेपथ्य में चली गई। इसके साथ ही यह सवाल भी निरर्थक हो गया कि एक एमबीबीएस पास व्यक्ति जब पीजी डिग्री के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहा है, तो वह कौन से कारण रहे होंगे कि उसका पास होना तो दूर, उसकी जीरो अंकों वाली सफलता भी उल्लेखनीय हो गई और इसी जीरो के आधार पर भी एडमिशन ऑफर किया जा रहा है।

इस विषय पर विचार करने से पहले दो पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पहला पहलू यह कि परसेंटाइल से अंक-प्रतिशत अथवा मेरिट के स्थान का निर्धारण नहीं होता। परसेंटाइल सिस्टम कई स्तरों पर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। परसेंटाइल व्यवस्था में यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति 60 परसेंटाइल के बावजूद प्रतिशत की दृष्टि से 25 प्रतिशत ही अंक प्राप्त कर सका हो। परसेंटाइल सिर्फ यह बताता है कि जितने लोगों ने परीक्षा दी है, संबंधित व्यक्ति उस परीक्षा में कितने लोगों से आगे है। यदि किसी बैच में कुल प्रदर्शन ही खराब हो, तो उच्च परसेंटाइल वाले व्यक्ति के वास्तविक अंक भी खराब हो सकते हैं। दूसरा पहलू यह कि नीट पीजी 2025 में एडमिशन कट ऑफ का जीरो परसेंटाइल तक गिरना कोई अचानक हुई घटना है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। जैसा कि मीडिया में बताया गया कि आरक्षित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया और इसके पीछे एक बात यह रही कि देश के संसाधन खराब न जाएं, उनका उपयोग आरक्षित वर्ग के लोगों को बेहतर शिक्षा देने में किया जाए। इस बात को मुख्यधारा के मीडिया ने जोर-शोर से परोसा, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। पीजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला हिस्सा सरकारी कॉलेजों का है, जहां हमेशा ही एडमिशन को लेकर मारामारी रहती है। इन कॉलेजों में आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स को भी ऊंची मेरिट होने पर ही प्रवेश मिल सकता है। इससे यह बात स्पष्ट है कि नीट पीजी का परसेंटाइल जीरो किए जाने से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की कोई संभावना नहीं बनती। दूसरे कॉलेज हैं, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर चलाता है और इनमें फीस इतनी अधिक है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के बारे में नहीं सोच सकता। यहां जिस सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, इस श्रेणी में ग्रुप-ए की नौकरी करने वाला सरकारी अधिकारी भी शामिल है। यदि वह अपने जीवन की सारी जमा-पूंजी जोड़ ले, तो भी शायद ही अपने एक बच्चे को मेडिकल की पीजी डिग्री करा सके।

अब इस बात का पुनः स्मरण कीजिए कि जीरो परसेंटाइल पर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में किन लोगों को एडमिशन मिलेगा। यह बात आपको शॉक जैसी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन युवाओं ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से जैसे-तैसे एमबीबीएस पास किया है, अब ज्यादातर वे ही युवा इन प्राइवेट कॉलेजों में पीजी मेडिकल डिग्री में प्रवेश प्राप्त करेंगे। इन युवाओं की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वे ऐसे परिवारों से आते हैं, जहां सालाना 20-30 लाख रुपए या इससे भी अधिक फीस चुकाने की आर्थिक क्षमता मौजूद है। आरक्षित वर्ग में ऐसे कितने लोग होंगे, जो इतनी बड़ी फीस चुकाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कतार में खड़े होंगे? अनुमान यही है कि यह संख्या नाममात्र की ही होगी। पीजी मेडिकल डिग्री में जीरो परसेंटाइल पर एडमिशन के मामले ने नए सिरे से यह साबित किया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं और आपके पास पूंजी का बड़ा संबल है, तो फिर विशिष्ट योग्यता बहुत मायने नहीं रखती।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में मेडिकल एजुकेशन एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गई है, जहां केवल दो प्रकार के युवा ही डॉक्टर बन सकते हैं। पहले वे हैं, जिन्हें उच्च स्तर की मेधा प्राप्त है (जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है) और दूसरी श्रेणी उन लोगों की है, जो प्राइवेट कॉलेजों में किसी भी स्तर की फीस चुकाकर एमबीबीएस और उसके बाद पीजी मेडिकल डिग्री हासिल कर सकते हैं। इनके बीच में लोअर और लोअर मिडिल क्लास के युवाओं के लिए एमबीबीएस और इसके बाद पीजी मेडिकल डिग्री एक असंभव सपने जैसी बन गई है।

नीट पीजी में जीरो और माइनस परसेंटाइल

के बाद मीडिया में कुछ ऐसे समाचार और विज्ञापन भी देखने को मिले, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात आईएमए के पदाधिकारियों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया। यह चिंताजनक संकेतक है, क्योंकि जिस आईएमए को चिकित्सा जैसे पेशे में उच्च पेशेवर मूल्यों की रक्षा और मेधा-संपन्न युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है, वही उन लोगों के साथ खड़ी दिखने लगी, जो जीरो परसेंटाइल के समर्थक हैं। हालांकि मेडिकल एजुकेशन के नियमन, प्रवेश प्रक्रिया के संचालन अथवा फीस आदि के निर्धारण में आईएमए की कोई सीधी भूमिका नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा शक्तिशाली समूह जरूर है, जो मेडिकल एजुकेशन की नीतियों को व्यापक स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आईएमए में ऐसे लोग शामिल हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और वे इतनी क्षमता रखते हैं कि मेडिकल की रेगुलेटरी बॉडी नेशनल मेडिकल काउंसिल के जरिए अपना एजेंडा लागू करवा सकते हैं।

बार-बार यह कहा जा रहा है कि भारत में डॉक्टरों की कमी है, इसलिए किसी भी स्तर पर मेडिकल की सीटें खाली नहीं रखी जानी चाहिए, चाहे उन सीटों पर अयोग्य लोगों को ही एडमिशन देना पड़े। जबकि भारत में अब WHO के मानकों से अधिक संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हो चुके हैं। विगत वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगातार बढ़ी है।

हालांकि नए मेडिकल कॉलेजों की एजुकेशन गुणवत्ता अभी वैसी नहीं है, जैसी पुराने मेडिकल कॉलेजों में रही है, फिर भी सरकारी कॉलेजों के मामले में एक बात पर संतोष किया जा सकता है कि एक तो यहां फीस तुलनात्मक रूप से कम है और दूसरे, मेडिकल कॉलेजों के साथ जुड़े अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बहुत होती है, इसलिए भावी डॉक्टरों को अच्छी ट्रेनिंग मिलने की संभावना रहती है।

क्या उपर्युक्त बात को सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू किया जा सकता है? इस सवाल का बहुत स्पष्ट उत्तर वे लोग दे सकते हैं, जो मेडिकल एजुकेशन के स्याह पहलुओं को जानते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्या ऐसे प्राइवेट संस्थानों की है, जिनकी एजुकेशन गुणवत्ता बहुत संतोषजनक नहीं है।

यदि मेडिकल एजुकेशन को उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाए रखना है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस के निर्धारण पर कड़े मानक लागू किए जाने की आवश्यकता है। इन कॉलेजों के मामले में यह तर्क दिया जाता है कि कॉलेज चलाने वालों ने बहुत मोटा पैसा निवेश किया है, इसलिए सीटों को खाली छोड़ना उचित नहीं होगा। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि खाली सीटों पर सरकारी सीटों का कोटा बढ़ाया जाए और इन सीटों पर उन लोगों को एडमिशन दिया जाए, जो ऊंची मेरिट वाले हैं, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं पा सके हैं। इससे संसाधनों के सदुपयोग की बात भी पूरी हो जाएगी और सुयोग्य लोगों को मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण पेशे में आने का अवसर मिलेगा।

इस क्रम में यह भी याद रखे जाने की आवश्यकता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम फीस से पढ़े डॉक्टरों से ही यह उम्मीद की जा सकती है कि वे डेढ़-दो लाख रुपए महीने के वेतन पर किसी सरकारी चिकित्सालय में सेवा देंगे। यह उम्मीद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के उन युवाओं से करना बेमानी होगी, जिन्होंने एक करोड़ रुपए की फीस खर्च करके एमबीबीएस और लगभग इतना ही खर्च करके पीजी मेडिकल डिग्री हासिल की है। इन दोनों डिग्रियों में दो करोड़ रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति शायद ही डेढ़-दो लाख रुपए महीने की सरकारी नौकरी की तरफ देखेगा भी। जिस परिवार ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वह जल्द से जल्द इस इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल भी हासिल करना चाहेगा। ऐसे में, मेडिकल पेशे की पवित्रता और डॉक्टर को भगवान जैसा मानने की अवधारणा औंधे मुंह पड़ी दिखाई देती है।

(लेखक चमनलाल पीजी कॉलेज, हरिद्वार के प्राचार्य है तथा वरिष्ठ स्तंभकार है)

एम्स ऋषिकेश की प्रोफेसर डॉ. भानु दुग्गल नियुक्त हुई एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नई कुलपति

डॉ भानु दुग्गल प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ तथा एम्म ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष है

देहरादून। एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. भानु दुग्गल को हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉ. दुग्गल का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त, अधिकतम पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश कुलाधिपति गुरमीत सिंह द्वारा जारी किया गया है।

राज्यपाल ने चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नई नियुक्ति की गई है। इस संबंध में जारी आदेश में पूर्व आदेश संख्या 27778, दिनांक 17 जनवरी 2026 को निरस्त कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम 2020 की धारा-10 की उपधारा (4) के अंतर्गत कुलपति चयन के लिए गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से धारा-10 की उपधारा (5) के खंड (ख) में निहित प्रावधानों के तहत एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. भानु दुग्गल को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है।

औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्वदेशी स्टार्टअप की सशक्त मिसाल

शिखा अग्रवाल

दिव्य हिमगिरि से *पूनम आर्य* की दिव्यमोल की संस्थापक शिखा अग्रवाल से खास बातचीत

अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा पृष्ठभूमि के बारे में बताएं

मेरा पालन-पोषण और शिक्षा हरि की नगरी हरिद्वार में हुई है। मेरा परिवार शिक्षित, अनुशासित और कर्मप्रधान मूल्यों में विश्वास रखने वाला रहा है। मेरे पिता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से संबद्ध भारत नवरत्न संस्थान में कार्यरत रहे हैं, जबकि मेरी माता जी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। माता-पिता से मुझे ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे संस्कार मिले, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार से पूर्ण की। इसके पश्चात मेरठ विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। परास्नातक की पढ़ाई मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज, ऋषिकेश से पूरी की। अध्ययन के दौरान मेरे प्राध्यापकों ने मुझे शोधात्मक सोच विकसित करने और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ने की प्रेरणा दी। विशेष रूप से पेड़-पौधों और औषधीय वनस्पतियों के प्रति मेरी रुचि इसी समय विकसित हुई।

आत्मनिर्भर बनने की इच्छा मेरे भीतर शुरू से ही रही है। मैं चाहती थी कि अपना स्वयं का कार्य करूँ और भविष्य में दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकूँ। आज अपने पति के सहयोग से मैं न केवल एक सफल वैवाहिक जीवन जी रही हूँ, बल्कि अपने सपनों को भी साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हूँ।

आपके प्रोफेशन या स्टार्टअप के बारे में बताएं और आप किससे प्रभावित हुई

मैं उत्तराखंड की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत से बचपन से परिचित रही हूँ। हमारे पहाड़ी क्षेत्र औषधीय जड़ी-बूटियों का विशाल भंडार हैं, जिनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग अभी भी सीमित रूप में ही हो पा रहा है। इसी सोच ने मुझे उत्तराखंड की पारंपरिक जड़ी-बूटियों पर गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया। अपने शोध के दौरान मैंने विशेष रूप से बिच्छू घास पर कार्य किया, जिसके औषधीय गुण अत्यंत प्रभावशाली हैं। वर्तमान में मैं बिच्छू घास से दर्द निवारक तेल, बालों के लिए पोषक तेल तथा हर्बल चाय जैसे उत्पाद तैयार कर रही हूँ। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने स्टार्टअप "दिव्यमोल" की शुरुआत की।

इस कार्य की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैंने अपनी माँ के जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए बिच्छू घास से तेल तैयार किया। जब उन्हें इससे वास्तविक लाभ मिला, तब मुझे महसूस हुआ कि यह ज्ञान केवल परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हित में भी इसका उपयोग होना चाहिए। मैं अपनी माँ और अपने पति की कार्यशैली, उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता से अत्यधिक प्रभावित रही हूँ। इसके साथ ही वे लोग भी मेरी प्रेरणा रहे हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखे और उन्हें साकार कर दिखाया।

आपकी उपलब्धियों के बारे में बताएं, आपने अब तक क्या कार्य किया है?

मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मेरे उत्पादों से लोगों को वास्तविक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आया है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया ने मुझे अपने कार्य के प्रति और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा दी, जिससे मेरा अनुभव और पहचान दोनों बढ़े।

हाल ही में विज्ञान धाम, देहरादून में आयोजित राज्य के छठे देहरादून अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव-2025 के अंतर्गत रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुझे मेरे उत्पादों और नवाचार के लिए राज्य नीति आयोग के निदेशक डॉ. मनोज पंत द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है।

आपके भविष्य की योजनाएँ क्या हैं?

भविष्य में मेरी योजना है कि मैं अपने स्टार्टअप "दिव्यमोल" को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तारित करूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा कार्य केवल आर्थिक सफलता तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो। आने वाले समय में मैं युवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों के लिए रोजगार एवं मार्गदर्शन के अवसर सृजित करना चाहती हूँ। मेरे उत्पाद वर्तमान में गूगल सर्च पर लोकप्रिय उत्पादों की सूची में ऊपर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जो मेरे लिए उत्साहवर्धक है। इसके साथ-साथ मैं बिच्छू घास से जुड़े अन्य उत्पादों पर भी निरंतर शोध कर रही हूँ, ताकि इसके औषधीय लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें।

आप हमारी पत्रिका के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी

मैं आपकी दिव्य हिमगिरि पत्रिका के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगी कि सपने देखना आवश्यक है, लेकिन उनसे भी अधिक जरूरी है उन सपनों के लिए निरंतर प्रयास करना। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखें, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती हैं। आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी के साथ किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और नीयत सच्ची हो तो सफलता अवश्य मिलती है।

पहाड़ों के बीच नया मार्ग बदलेगी देहरादून-मसूरी की दूरी

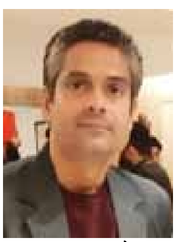

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

देहरादून से मसूरी का सफर आज भी घुमावदार मोड़ों, खतरनाक ढलानों और हर सीजन में लगने वाले लंबे जाम से जूझता है। बारिश हो या सैलानी सीजन, यह रास्ता अक्सर डर, देरी और परेशानी का दूसरा नाम बन जाता है। पहाड़ों के बीच बनने वाला नया मार्ग अब इसी मजबूरी को राहत में बदलने जा रहा है। इस सड़क के तैयार होते ही जहां जोखिम भरे मोड़ पीछे छूट जाएंगे, वहीं देहरादून से मसूरी तक की यात्रा न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होगी, बल्कि कहीं अधिक आसान और तेज भी बन जाएगी। देहरादून-मसूरी के बीच 42 किलोमीटर लंबा नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। करीब 3500 करोड़ रुपये की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की एलाइनमेंट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। नए मार्ग से जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और सैलानी घंटों के सफर की बजाय कम समय में मसूरी पहुंच सकेंगे। यह बदलाव सिर्फ दूरी कम करने का नहीं होगा, बल्कि पहाड़ों की उस थकाऊ और खतरनाक यात्रा को भरोसेमंद सफर में बदलने का होगा, जिसका इंतजार लोग वर्षों से कर रहे हैं।

देहरादून से पहाड़ों की रानी मसूरी का सफर वर्षों से उत्तराखंड की सुंदरता और उसकी मजबूरियों, दोनों का प्रतीक रहा है। एक ओर हर मोड़ पर खुलते पहाड़, बादलों से ढकी घाटियां और देवदार के जंगल हैं, तो दूसरी ओर वही घुमावदार सड़कें, खतरनाक ढलान, हर सीजन में लगने वाला जाम और जरा-सी बारिश में बढ़ता डर। पर्यटन सीजन हो या छुट्टियों का समय, मसूरी जाने वाला रास्ता अक्सर घंटों की परीक्षा बन जाता है। अब इसी मजबूरी से राहत की उम्मीद जगी है। मसूरी में लगने वाले जाम से जल्द निजात मिल सकती है, क्योंकि देहरादून-मसूरी के बीच 42 किलोमीटर लंबा नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। करीब 3500 करोड़ रुपये की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की एलाइनमेंट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सिर्फ एक सड़क की स्वीकृति नहीं है, बल्कि पहाड़ों में यात्रा और यातायात की सोच बदलने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के लिए वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान को सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि पहाड़ों की संवेदनशील भूगर्भीय संरचना को ध्यान में रखते

हुए सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

इस नए हाईवे में अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना के तहत जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र के नीचे लगभग 2.9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जबकि मसूरी की पहाड़ियों में करीब 2 किलोमीटर लंबी दूसरी सुरंग प्रस्तावित है। ये सुरंगें उस खतरनाक और समय लेने वाले चढ़ाई-उतराई वाले रास्ते का विकल्प बनेंगी, जो आज देहरादून से मसूरी के बीच सबसे बड़ी चुनौती है। नया हाईवे देहरादून के झाझरा क्षेत्र से शुरू होकर सीधे मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक पहुंचेगा। इसके पूरा होने के बाद न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा का समय भी काफी घट जाएगा और जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना ऐसे समय में सामने आई है, जब सरकार देहरादून और आसपास के पहाड़ी शहरों में यातायात दबाव को कम करने के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में प्रस्तावित पॉड टैक्सी परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मसूरी और नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की कवायद तेज करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना तथा मसूरी और नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान परियोजनाओं के तकनीकी, सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। बताया गया कि देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना को ईबीआरटीएस के फीडर सिस्टम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम किया जा सके। पीआरटी परियोजना के तहत तीन प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। क्लेमेंटाउन से बल्लूपुर चौक, पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन और गांधी पार्क से आईटी पार्क तक। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती देगी। बैठक में निगम द्वारा तैयार की गई डीपीआर पर गहन चर्चा हुई और आवास सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना की आवश्यकता, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, सामाजिक प्रभाव और वित्तीय व्यवहार्यता को और अधिक ठोस रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठक में संशोधित डीपीआर के साथ दोबारा प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश भी दिए। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी कॉरिडोर के संरेखण का स्थलीय निरीक्षण करने की इच्छा भी जताई, ताकि जमीनी स्तर पर परियोजना की व्यवहारिकता का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। इसके साथ ही मसूरी और नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक ने अवगत कराया कि रोपवे परियोजनाएं पर्वतीय शहरों में यातायात जाम, पार्किंग की समस्या और प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आवास सचिव ने रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि का विस्तृत विवरण, स्वामित्व की स्थिति सहित तैयार करने और संबंधित विभागों से पत्राचार

मसूरी और आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी

देहरादून-मसूरी नया राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसी कड़ी के रूप में उभर रहा है, जो पहाड़ों की यात्रा का चेहरा बदल सकती है। यह सड़क सिर्फ वाहनों की आवाजाही का माध्यम नहीं होगी, बल्कि यह उस मानसिक दूरी को भी कम करेगी, जो आज लोग मसूरी जाने से पहले महसूस करते हैं। जाम का डर, हादसों की आशंका और समय की अनिश्चितता। नए मार्ग के बाद मसूरी जाना महज एक खूबसूरत सफर रह जाएगा, न कि एक चुनौती। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को उम्मीद है कि इस परियोजना से न सिर्फ पर्यटकों को राहत मिलेगी, बल्कि मसूरी और आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। होटल व्यवसाय, स्थानीय दुकानदार और टैक्सी चालक सभी को बेहतर कनेक्टिविटी से सीधा लाभ मिलेगा। आपातकालीन सेवाओं के लिए भी यह मार्ग जीवनरेखा साबित हो सकता है, क्योंकि कम समय में सुरक्षित पहुंच संभव हो सकेगी। हालांकि, पहाड़ों में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी जुड़ी रहती हैं। ऐसे में वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, ताकि निर्माण के दौरान भूस्खलन, जलस्रोतों और पारिस्थितिकी पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। यदि संतुलन और संवेदनशीलता के साथ यह परियोजना पूरी होती है, तो यह उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य का एक उदाहरण बन सकती है। देहरादून-मसूरी नया मार्ग, पॉड टैक्सी और रोपवे जैसी योजनाएं मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं, जिसमें पहाड़ों की सुंदरता सुरक्षित रहे और यात्रा आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। यह सिर्फ सड़कों और सुरंगों की कहानी नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की कहानी है, जिसमें उत्तराखंड का भविष्य जाम और डर से नहीं, बल्कि सुगम रास्तों और संतुलित विकास से तय होगा।

कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि संबंधी पहलुओं का समयबद्ध समाधान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना और मसूरी व नैनीताल में रोपवे परियोजनाएं राज्य के लिए महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनसे यातायात दबाव कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी परियोजनाओं को पारदर्शी, व्यावहारिक और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

देहरादून से मसूरी अब डर नहीं सुकून का होगा सफर

गढ़वाल की गोद में बसी पहाड़ों की रानी मसूरी हमेशा से सैलानियों की पहली पसंद रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से लोग मसूरी की ठंडी हवा, बादलों की ओट और माल रोड की रौनक का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन इस खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अक्सर उतना ही कठिन और डरावना साबित होता है। देहरादून से मसूरी के बीच घुमावदार सड़क, तीखे मोड़, भारी ट्रैफिक और सीजन में लगने वाला लंबा जाम सैलानियों की खुशी को कई बार सफर में ही थका देता है। अब हालात बदलने की उम्मीद जगी है। देहरादून-मसूरी के बीच प्रस्तावित नया मार्ग मसूरी आने वाले सैलानियों के लिए राहत की बड़ी सौगात बन सकता है। यह मार्ग बन जाने के बाद न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा ज्यादा सुरक्षित, सुगम और सुखद हो जाएगी। अब तक जहां मसूरी पहुंचने में घंटों लग जाते थे, वहीं नए मार्ग से कम समय में पहाड़ों की रानी तक पहुंचना संभव हो सकेगा। खासतौर पर वे परिवार, बुजुर्ग और महिला पर्यटक, जो अब तक खतरनाक मोड़ों और जाम के डर से मसूरी जाने से कतराते थे, उनके लिए यह बदलाव बेहद अहम होगा। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि यह नया मार्ग मसूरी के पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। देहरादून एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से मसूरी की कनेक्टिविटी आसान होने से बाहर से आने वाले सैलानी सीधे और सुरक्षित तरीके से पहाड़ों तक पहुंच सकेंगे। इससे न सिर्फ सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उनका अनुभव भी पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक होगा। जाम में फंसे बिना, बिना घबराहट के पहाड़ों के बीच सफर करना मसूरी यात्रा को यादगार बना देगा। स्थानीय होटल व्यवसायियों और टैक्सी चालकों को भी इस मार्ग से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि जब सफर आसान और भरोसेमंद होगा, तो लोग मसूरी में ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे होटल बुकिंग, स्थानीय बाजार और रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। मसूरी सिर्फ वीकेंड डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक आरामदायक हिल स्टेशन के रूप में और मजबूत पहचान बना सकेगी। यह मार्ग सिर्फ सैलानियों की सुविधा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपात सेवाओं के लिए भी वरदान साबित होगा। दुर्घटना, बीमारी या किसी आपदा की स्थिति में देहरादून से मसूरी तक तेज और सुरक्षित पहुंच संभव हो सकेगी। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बनेगा। देहरादून-मसूरी के बीच बनने वाला नया मार्ग पहाड़ों की रानी तक पहुंचने के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। जहां आज सफर में डर और देरी जुड़ी है, वहीं आने वाले समय में यही यात्रा सुकून, सुरक्षा और आनंद का पर्याय बन सकती है। मसूरी का क्रेज तो पहले से ही चरम पर है, अब रास्ता भी उसी खूबसूरती और भरोसे के काबिल बनने जा रहा है।

राज्यपाल ने किया देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "परीक्षा पे चर्चा-2026" कार्यक्रम में प्रतिभाग

राज्यपाल ने सचिव, विद्यालय शिक्षा रविनाथ रमन एवं प्रमुख शिक्षाविद राकेश ऑबराय के साथ ओएसिस स्कूल, रायपुर, देहरादून में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ''परीक्षा पे चर्चा'' न केवल छात्रों की शंकाओं का समाधान करता है, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों को भी सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा को बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने ज्ञान और क्षमताओं को परखने का अवसर मानें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति केवल सपने देखने से नहीं होती, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर प्रयास से संभव होती है। इच्छाशक्ति को निरंतर कर्म से जोड़ना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने का अवसर है। प्रश्न को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब प्रश्न स्पष्ट होता है, तभी उत्तर भी सही और सार्थक होता है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों को स्वीकार करने का आह्वान किया और कहा कि कठिन परिश्रम से ही आत्मविश्वास का निर्माण होता है।

उन्होंने कर्म और कर्तव्य को जीवन का मूल आधार बताते हुए कहा कि प्रत्येक कर्म उसका परिणाम अवश्य देता है। उन्होंने कहा कि जीवन की वास्तविक प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने से होती है। यही सोच व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाती है और राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। इस कार्यक्रम में सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, स्कूल के चेयरमैन राकेश ओबेरॉय, निदेशक राघव ओबेरॉय, प्रधानाचार्य संजीव बाटला तथा स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती उत्तराखंड की जनजातीय महिलाएँ

डॉ. प्रियंका पांडेय

भारत में विभिन्न समुदाय, भाषाएँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ आपस में मिलकर एक बहुआयामी और विविधताओं से भरा अद्वितीय सामाजिक ताना-बाना तैयार करती हैं, जिसमें प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ जनजातीय समाज अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जनजातीय समुदायों का योगदान न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम भूमिका निभाता है, जिसमें महिलाएँ सदियों से परिवार और समाज की धुरी की तरह रही हैं। खेती-बाड़ी, पशुपालन, वनों से संसाधन जुटाना, हस्तशिल्प निर्माण और सामाजिक जीवन की संरचना में उनकी भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान में इन जनजातीय महिलाओं में केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित ना रहकर उद्यमिता की ओर आगे बढ़ने की गहरी आकांक्षाऐं पनपती हुई दिखाई दे रही हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढने और सम्मानजनक जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है।

उत्तराखंड की जनजातीय महिलाएँ यहां की भौगोलिक चुनौतियाँ, सीमित संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, तथा पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के चलते लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में जीवन जीती आ रही हैं, जो इनके जीवन को भी प्रभावित करता है। चूंकि इन महिलाओं में निहित धैर्य, परिश्रम और पारंपरिक ज्ञान उन्हें एक विशेष पहचान प्रदान करता है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि यदि इन्हें उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाए तो यह महिलाएँ न केवल अपने परिवारों का सही तरह से भरण-पोषण कर सकने में सक्षम हो सकती हैं, बल्कि पूरे समाज की आर्थिक स्थिति को भी बदल सकती हैं।

महिला उद्यमिता का अर्थ केवल एक व्यवसाय प्रारंभ करना ही नहीं है, बल्कि यह उनके लिए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। जब कोई महिला उद्यमी बनती है, तो वह अपने साथ-साथ अन्य महिलाओं और समुदाय के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करती है। उत्तराखंड की जनजातीय महिलाओं के पास ऐसा अद्भुद पारंपरिक ज्ञान है, जिसे आधुनिक बाजार की मांग और आपूर्ति के साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, बांस और रिंगाल से बनी वस्तुएँ, ऊनी वस्त्र, जड़ी-बूटियों से बने उत्पाद, स्थानीय खानपान, और हस्तशिल्प आदि को ब्रांडिंग और बाजारीकरण (मार्केटिंग) के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यवसाय और व्यापार में बदला जा सकता है। प्रश्न यहाँ यह उठता है, कि इन महिलाओं को उद्यमिता की राह में कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें सबसे पहली चुनौती है, संसाधनों और पूँजी की कमी, क्योंकि अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ और वित्तीय संस्थान प्रायः दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जिससे इन महिलाओं को ऋण या पूँजी प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है, शिक्षा और वित्तीय साक्षरता की कमी, क्योंकि उद्यमिता के लिए केवल मेहनत और उत्पाद निर्माण ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बाजार की समझ, वित्तीय प्रबंधन और विपणन की रणनीतिक जानकारी का भी होना उतना ही आवश्यक है। एक तीसरी चुनौती सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं की भी है, जो अक्सर इन महिलाओं को पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के कारण स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी नहीं प्रदान कर पाती है। इसके अलावा एक चौथी चुनौती भी बाजार तक पहुँच बनाने की है, क्योंकि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचाना एक बेहद कठिन और मुश्किल भरा कार्य है।

हालांकि आज के परिदृश्य में इन सभी चुनौतियों के बावजूद, अवसरों की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण जीवन, जैविक खेती और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्यटन का क्षेत्र अब यहाँ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कृषि पर्यटन (एग्रो-टूरिज्म), जो कि एक ऐसा व्यवसायिक मॉडल विकसित हुआ है, जिसमें पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, उत्सव, प्रकृति का अनुभव, खेती-किसानी और ग्रामीण जीवन के अनुभव के साथ फार्म-स्टे, फार्म-टू-टेबल भोजन, फसल कटाई में भागीदारी और ग्रामीण गतिविधियाँ जैसे ऊंट, बैलगाड़ी आदि की सवारी से जोड़कर देखा जाता है, में इन महिलाओँ की भागीदारी एक महत्वपूण

ी भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार धीमा पर्यटन (स्लो-टूरिज्म) भी आजकल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, जिसमें पर्यटक किसी एक स्थान पर अधिक समय तक रहकर यात्रा का आनंद ले सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में धीमे पर्यटन के क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई है। इटली में स्लो फूड मूवमेंट के बाद धीमे पर्यटन (स्लो टूरिस्म) की शुरुआत हुई थी। कार्लो पेट्रिनी नामक व्यक्ति ने कम दामों पर ऑर्गेनिक भोजन को बेचकर लोगों तक सेहतमंद और क्वालिटी भोजन की पहुंच को सुनिश्चित किया था, जिससे लोग अच्छे खाने का मजा ले सकें। स्लो टूरिस्म का उद्देश्य पर्यटकों को सुकून से रहने और कम से कम भागदौड़ के साथ स्थानीय स्थानों की सैर करना, मेल-मिलाप करना और ईको फ्रेंडली उत्पादों को करीब से जानने और समझने के साथ-साथ नए व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। अतः इस तरह के पर्यटनों की उत्तराखंड में अपार सम्भावना है, जिसमें जनजातीय महिलाओं की भागीदारी बढाई जा सकती है। यदि महिलाओं को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए, तो वे सम्भवतः वह अपने घरों को होम-स्टे के रूप में विकसित कर सकती हैं और अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकती हैं।

इसी तरह, इनके द्वारा निर्मित "स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पाद" जैसे ऊनी कपड़े, जड़ी-बूटियों से बने औषधीय उत्पाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है। वेलनेस और हर्बल उद्योग भी एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। महिलाएँ यदि इनसे उत्पाद निर्माण और विपणन का कार्य करें तो यह न केवल उनकी आजीविका का साधन बनेगा बल्कि वैश्विक बाजार में उनकी पहचान भी स्थापित करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ महिलाएँ पहाड़ी व्यंजनों जैसे मंडुए की रोटी, झंगोरे की खीर, भांग की चटनी और स्थानीय दालों को पैकिंग और मार्केटिंग के साथ-साथ बड़े पैमाने पर इसे अपने निजी व्यवसाय में बदल सकती हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों ने भी इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य सरकार की स्वयं सहायता समूह योजनाएँ, और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाएँ जनजातीय महिलाओं को उद्यमिता

कृषि पर्यटन की ओर बढता उत्तराखंड

की ओर प्रेरित कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ आपस में मिलकर बचत करती हैं, और छोटे-छोटे व्यवसाय आरंभ करती हैं। इन समूहों ने अनेक गाँवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है।

कुछ सफल जनजातीय महिलाओं के उदाहरण भी हमारे सामने हैं, जैसे की उत्तराखंड की कई महिलाओं ने मशरूम का उत्पादन, बकरी पालन, बांस और रिंगाल की वस्तुओं को बनाने तथा जैविक खेती को अपनाने के माध्यम से उद्यमिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मशरूम क्वीन के नाम से प्रसिद्ध दिव्या रावत ने यह साबित किया है, कि यदि सही दृष्टिकोण और मार्गदर्शन मिले तो महिलाएँ बड़े स्तर पर उद्यमिता को अवसर में बदल सकती हैं। इसी प्रकार से अनेक स्थानीय महिलाओं ने अपने छोटे-छोटे समूहों के माध्यम से ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प कला और स्थानीय व्यंजनों का व्यवसाय प्रारंभ करके रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त किए हैं।

जनजातीय महिलाओं की उद्यमिता न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का साधन है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान देती हैं। इसका सीधा लाभ उनके बच्चों और पूरे परिवार को मिलता है। महिलाएँ यदि वित्तीय निर्णयों में भागीदारी करें, तो वह परिवार की आय का सही उपयोग अधिक प्रभावी और संतुलित ढंग से कर सकती हैं। इससे सामाजिक असमानता तो कम होती ही है, सामुदायिक विकास की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। आने वाले दिनों में हमें यह समझना होगा, कि जनजातीय महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना ना केवल सरकारी नीतियों तक ही सीमित होना चाहिए, बल्कि भविष्य की दिशा में यह समाज के सभी वर्गों की भी यह एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, कि कैसे इन महिलाओं के हितों के साथ-साथ उनकी कार्य कुशलता को सराहा और प्रोत्साहित किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों को भी ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए, जो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं आर्थिक व सामाजिक स्थिती को बढाने के लिए रोजगार परक और उपयुक्त हों, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन विपणन आदि की जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

आज के युग में ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए बड़े-बढे अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि जनजातीय महिलाएँ भी अपने उत्पादों को डिजिटल माध्यम से बाजार में बेच सकें तो यह उनके लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। अंत में यह कहा जा सकता है, कि उत्तराखंड की जनजातीय महिलाएँ पर्वतीय समाज में रीढ़ की तरह हैं, क्योंकि उनके पास पारंपरिक ज्ञान और परिश्रम की वह अद्भुद शक्ति है, जो उन्हें उद्यमिता की दिशा में आगे ले जा सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है, कि उनके लिए सही मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। यदि इन महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगें, तो वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगी, बल्कि पूरे समाज को आत्मनिर्भरता और सतत विकास की ओर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

वास्तव में आज के समय में महिला उद्यमिता केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, समानता और समावेशी विकास का वह रास्ता (राह) है, जिससे उनके परिवार की इमारत के साथ-साथ इस देश की नींव भी मजबूत होने वाली है। उत्तराखंड की जनजातीय महिलाएँ यदि इस राह पर आगे बढ़ेंगी, तो सम्भवतः वह न केवल अपने समुदाय बल्कि इस पूरे राज्य और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगी।

खून से लथपथ हुआ देहरादून का 'हृदय'

देहरादून की पहचान हमेशा एक शांत, सुकून भरे और सुरक्षित शहर के रूप में रही है, लेकिन पलटन बाजार में दिनदहाड़े हुई इस निर्मम हत्या ने उस छवि को खून से सना हुआ कर दिया। जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करते हैं, महिलाएं बेखौफ आवाजाही करती हैं और पुलिस गश्त के दावे किए जाते हैं। वहीं एक युवती की गला काटकर हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पल भर में चहल-पहल से भरा बाजार मातम और खौफ में बदल गया। लोग सहमे हुए हैं, दुकानों के शटर गिर गए और सवाल गूंजने लगे। क्या देहरादून अब भी सुरक्षित है? यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि राजधानी की कानून-व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर सीधी चुनौती बनकर सामने आया है। सीसीटीवी कैमरों, गश्त और चौकियों के बीच हुई वारदात ने पुलिस के तमाम दावों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। घटना के बाद व्यापारियों और आम लोगों में भारी आक्रोश है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर और असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। शांत पहाड़ों की गोद में बसे देहरादून में अगर बाजारों के बीच ऐसी वारदात हो सकती है, तो सवाल सिर्फ पलटन बाजार का नहीं, पूरे शहर की सुरक्षा का है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

शांत, सुकून भरे और सुरक्षित शहर की पहचान रखने वाली उत्तराखंड की राजधानी देहरादून उस वक्त सन्न रह गई, जब शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले पलटन बाजार में दिनदहाड़े एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। जिस जगह हर समय हजारों की संख्या में खरीदार, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे मौजूद रहते हैं, जहां पुलिस गश्त और सीसीटीवी कैमरों के दावे किए जाते हैं, वहीं इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर की कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कुछ ही पलों में चहल-पहल से गुलजार बाजार खौफ, चीख-पुकार और मातम में बदल गया। दुकानों के शटर गिरने लगे और देहरादून की शांति खून से सनी नजर आई। यह सनसनीखेज हत्याकांड दोपहर के समय हुआ, जब पलटन बाजार में सामान्य दिनों की तरह भारी भीड़ मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक युवक अचानक युवती के पास पहुंचा और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते या संभल पाते, आरोपी ने युवती का गला रेत दिया। चंद सेकेंड में युवती जमीन पर गिर पड़ी और बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे, कुछ ने साहस दिखाकर मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक युवती गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे देहरादून को झकझोर कर रख दिया। पलटन बाजार, जिसे राजधानी का सबसे सुरक्षित और व्यस्त इलाका माना जाता है, वहां इस तरह की वारदात होना आम लोगों के लिए अकल्पनीय था। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि अगर इतनी भीड़ और पुलिस व्यवस्था के बीच भी कोई अपराधी खुलेआम हत्या कर सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा रह जाता है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर और आक्रोश खुलकर सामने आया। घटना के बाद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह स्वयं सक्रिय हुए। उन्होंने बताया कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार यह एक जघन्य अपराध है और पुलिस इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में आरोपी और मृतका के बीच जान-पहचान और निजी विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी किस मकसद से हथियार लेकर बाजार पहुंचा, यह भी जांच का अहम हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फिलहाल कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम की कड़ियां और स्पष्ट होंगी। वहीं मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक युवा जिंदगी का इस तरह बीच बाजार खत्म हो जाना न सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चोट है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हत्याकांड का असर सिर्फ पलटन बाजार तक सीमित नहीं रहा। पूरे

शहर में दहशत का माहौल है। लोग शाम ढलते ही घरों में सिमटने लगे हैं। सोशल मीडिया पर राजधानी की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस काम की है, जब सबसे व्यस्त बाजार में भी कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और गहरी हो गई है। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह घटना प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। देहरादून जैसे शहर में, जिसे उत्तराखंड की सबसे सुरक्षित राजधानी माना जाता है, इस तरह की वारदात यह बताती है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी चूक है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रभावी बनाना होगा। साथ ही अपराधियों में कानून का डर पैदा करने के लिए सख्त और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। पलटन बाजार में बहा यह खून सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे पर हमला है, जो लोग अपने शहर और व्यवस्था पर करते आए हैं। शांत पहाड़ों की गोद में बसे देहरादून की पहचान को इस घटना ने गहरी ठेस पहुंचाई है। अब सवाल यह है कि क्या यह हत्याकांड सिस्टम को झकझोर कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर कुछ दिनों बाद यह भी एक और खबर बनकर फाइलों में दबा दी जाएगी।

कांग्रेस ने धामी सरकार की कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया

देहरादून के पलटन बाजार में हुई जघन्य हत्या के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमा गई। राजधानी के सबसे भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सीधे तौर पर धामी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का खुला प्रमाण है, जिसने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देहरादून को अब तक एक शांत और सुरक्षित राजधानी माना जाता था, लेकिन पलटन बाजार जैसी जगह पर दिनदहाड़े हत्या होना सरकार और पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जहां हर समय हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, पुलिस गश्त और सीसीटीवी कैमरों की बात की जाती है, वहीं इस तरह की घटना हो जाना यह साबित करता है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि धामी सरकार केवल कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि आम जनता, खासकर महिलाएं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार उन्हें नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अगर राजधानी के सबसे व्यस्त बाजार में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी, बल्कि सरकार को यह भी बताना होगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम क्या उठाए जा रहे हैं। गणेश गोदियाल ने मांग की कि पलटन बाजार समेत सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और महिला सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था कमजोर हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पलटन बाजार हत्याकांड के बाद कांग्रेस के इस तीखे हमले से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक रूप से और तूल पकड़ सकता है। विपक्ष इसे जनता की सुरक्षा से जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति में जुट गया है, जबकि अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि धामी सरकार इस चुनौती का जवाब केवल बयानों से देती है या जमीन पर ठोस कार्रवाई कर भरोसा बहाल करती है।

हत्या से पहले युवती ने लगाई थी गुहार, पुलिस को दी शिकायत, अनसुनी रह गई चेतावनी

देहरादून के पलटन बाजार में हुई युवती गुंजन की नृशंस हत्या के मामले में चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गुंजन ने हत्या से पहले पुलिस से शिकायत की थी और अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी, लेकिन उस शिकायत पर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस ने समय रहते शिकायत को गंभीरता से लिया होता, तो शायद आज गुंजन जिंदा होती, यह सवाल अब पूरे शहर में गूंज रहा है। परिजनों के मुताबिक गुंजन पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव और डर में थी। उन्होंने बताया कि एक युवक द्वारा लगातार परेशान किए जाने की बात गुंजन ने परिवार को भी बताई थी। इसी को लेकर उसने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद न तो आरोपी को सख्त चेतावनी दी गई, न ही किसी तरह की निगरानी या सुरक्षा व्यवस्था की गई। नतीजा यह हुआ कि पलटन बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े गुंजन की हत्या कर दी गई। इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी के सबसे व्यस्त बाजार में हुई इस वारदात ने पहले ही कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, अब यह बात सामने आना कि मृतका ने पहले ही खतरे की आशंका जताई थी, पुलिस की लापरवाही के आरोपों को और गहरा कर रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि महिलाओं की शिकायतों को अक्सर हल्के में लिया जाता है, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शिकायत की प्रकृति और उस पर हुई कार्रवाई की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह देखा जा रहा है कि शिकायत कब और किस थाने में दी गई थी तथा उस पर क्या कदम उठाए गए। पुलिस का दावा है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुंजन की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई चाहते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता है, जिसने एक युवती की जान ले ली। यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रहा। यह महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की संवेदनशीलता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत का बड़ा सवाल बन गया है। पलटन बाजार में बहा खून अब जवाब मांग रहा है, कि आखिर गुंजन की शिकायत क्यों अनसुनी रह गई और क्या इस चूक की जिम्मेदारी तय होगी।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अध्याय खत्म

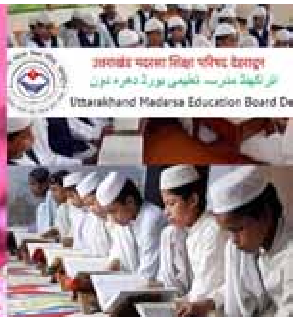

उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लेते हुए साफ संकेत दे दिया है कि अब धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक और मुख्यधारा की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाएगी। जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले इस निर्णय के बाद राज्य में संचालित मदरसों की शैक्षणिक संरचना, पाठ्यक्रम और निगरानी व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। सरकार का तर्क है कि यह कदम बच्चों को केवल एक सीमित ढांचे तक सीमित रखने के बजाय उन्हें व्यापक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए उठाया गया है, ताकि वे आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों तक पहुंच बना सकें। विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार नया प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सभी शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन राज्य की समग्र शिक्षा नीति के अनुरूप हों। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट)

उत्तराखंड की शिक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लेते हुए राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और उसकी जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि उस सोच का संकेत है जिसमें सरकार शिक्षा को धर्म या परंपरा की सीमाओं से बाहर निकालकर मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले इस फैसले के साथ ही दशकों से चली आ रही मदरसा बोर्ड की व्यवस्था औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी और प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा की दिशा, दशा और ढांचा पूरी तरह नए सिरे से तय होगा। राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा मदरसा बोर्ड प्रणाली बच्चों को सीमित पाठ्यक्रम तक बांध देती थी, जिससे वे आधुनिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार की दौड़ में पिछड़ जाते थे। सरकार अब चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी वही अवसर प्राप्त करें, जो किसी अन्य सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मदरसा बोर्ड को खत्म कर एक व्यापक और एकीकृत राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार नया प्राधिकरण न केवल मदरसों बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अन्य शैक्षणिक संस्थानों की भी निगरानी करेगा। इसके तहत पाठ्यक्रम, शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मूल्यांकन को राज्य की शिक्षा नीति के अनुरूप किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा और तकनीकी शिक्षा जैसे विषयों में मजबूत आधार मिलेगा, जिससे वे भविष्य में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। फिलहाल राज्य में बड़ी संख्या में मदरसे संचालित हैं, जिनमें हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन मदरसों की निगरानी अब तक मदरसा बोर्ड के माध्यम से होती थी, लेकिन बोर्ड की कार्यप्रणाली और पाठ्यक्रम को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई बार यह आरोप लगे कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और वे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रह जाते हैं। सरकार के इस फैसले को इन्हीं आलोचनाओं के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण एक नियामक संस्था के रूप में काम करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई का स्तर गिरने न पाए। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम सामाजिक समरसता को भी मजबूत करेगा, क्योंकि इससे सभी समुदायों के बच्चे एक समान शैक्षणिक ढांचे में आगे बढ़ सकेंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का तर्क है कि यह निर्णय बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं कुछ संगठनों और नेताओं का कहना है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करना परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में दखल है और इसे समुदाय की पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि किसी भी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि शिक्षा को और व्यापक बनाया जाएगा। सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि जुलाई 2026 तक एक संक्रमण काल रहेगा, जिसमें मदरसों को नए ढांचे के अनुरूप ढलने का समय मिलेगा। इस दौरान पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षकों के प्रशिक्षण और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर काम किया जाएगा, ताकि अचानक किसी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो।

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से क्या बदलेगा

मदरसा बोर्ड के स्थान पर बनने वाला राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नई भूमिका निभाएगा। यह प्राधिकरण केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीति निर्माण, पाठ्यक्रम सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे अहम कार्यों को भी संभालेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र शिक्षा के हर स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें और उन्हें अलग-थलग न रहना पड़े। नए प्राधिकरण के तहत मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छात्रों को वही शैक्षणिक सामग्री मिले, जो अन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही धार्मिक शिक्षा को एक विषय के रूप में बनाए रखने की संभावना भी जताई जा रही है, ताकि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कायम रखा जा सके। सरकार का कहना है कि उद्देश्य किसी व्यवस्था को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे समय के अनुरूप ढालना है। प्राधिकरण शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण पर भी खास जोर देगा। कई मदरसों में अब तक प्रशिक्षित शिक्षकों

की कमी एक बड़ी समस्या रही है। नए ढांचे में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की जाएगी और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पढ़ाई का स्तर सुधरने और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का सामाजिक असर भी व्यापक हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब मदरसों के छात्र मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे, तो उनके लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यह फैसला आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे सरकार की नीतियों से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष इसे शिक्षा सुधार के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले महीनों में इस विषय पर बहस और तेज होने की संभावना है, खासकर तब जब नया प्राधिकरण अपने स्वरूप और कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। धामी सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम करेगा। संस्थानों की नियमित जांच, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और वित्तीय प्रबंधन पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता न हो। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का समाप्त होना और राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन शिक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह फैसला जहां एक ओर परंपरागत ढांचे को चुनौती देता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अधिक समावेशी और आधुनिक बनाने की कोशिश भी है। जुलाई 2026 के बाद यह साफ हो जाएगा कि यह बदलाव कितनी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतर पाता है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को किस दिशा में ले जाता है।

स्कूली बच्चों की सभी वैन, ऑटो, बसों को लेना होगा आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्रः डॉ गीता खन्ना

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मा० अध्यक्ष महोदया डा० गीता खन्ना द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के आवागमन हेतु चल रही स्कूल वैन/बस/तीन पहिया वाहन/ऑटो/ई-रिक्शा आदि के सत्यापन, उनकी मॉनिटरिंग व नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05.02. 2026 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद देहरादून से सम्भागीय परिवहन अधिकारी डा० अनीता चमोला व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव उपस्थित हुये तथा अन्य समस्त जनपदों द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई। आयोग की ओर से डा० शिव कुमार बरनवाल, सचिव व डा० सतीश कुमार सिंह, अनुसचिव उपस्थित हुए। बैठक में मा० अध्यक्ष महोदया डॉ० गीता खन्ना द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे वाहन जो कि स्कूल से बच्चों को लाना-लेजाना कर रहे है, किन्तु उन्हें स्कूल द्वारा निर्धारित नही किया गया है। स्कूलों के बच्चों को लाने -लेजाने वाली प्राईवेट गाडियों (जैसे वैन, ऑटो, विक्रम इत्यादि) को आर०टी०ओ० से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्देश दिये गये तथा उनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है व स्कूलों में भी उनका रिकार्ड होना जरूरी है, जिसमें ड्राईवरों का पूर्ण विवरण व मनौस्थिति की जांच रिपोर्ट भी रक्षित हो। मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा स्कूलों में बच्चों को लाने -ले जाने के लिये चल रही प्राईवेट वाहनों को चिन्हित किये जाने के लिये एक यल्लों स्ट्रिप लगाये जाने हेतु सुझाव दिया गया, जिससे वाहन चिन्हित हो जाये कि वाहन में बच्चे यात्रा कर रहे है तथा उन प्राईवेट वाहनों को वाहन स्वामी अपने अन्य कार्य के लिये भी प्रयोग में ला सके। स्कूलों में बच्चें किस ट्रांसपोर्ट मोड से आना-जाना कर रहे है, उसका पूर्ण विवरण स्कूलों के पास रक्षित होना चाहिये। मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा जनपदवार परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण सुना गया, जिसके उपरान्त उनके द्वारा जनपद बागेश्वर की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुये उनके अनुरूप कार्य किये जाने हेतु कहा गया तथा साथ ही अपनी कार्यप्रणाली को आयोग के साथ सांझा किये जाने की बात कही गयी। मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी जनपदों को उनके समक्ष आ रही चुनौतियों, कठिनाईयों व उनके सुझाव को भी आयोग के उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा समय समय पर स्कूलों में जाकर बच्चों को रोड सेफ्टी प्रशिक्षण कराया जाता है, इसके लिए आगे भी ट्रेनिंग व प्रशिक्षण करने के लिए अपने नए मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हर क्षेत्र में ब्लेक स्पाट्स भी चिन्हित है तथा प्रत्येक माह लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि स्कूल बसों को भी एक्सीडेंट रिलिफ फण्ड से कवर किया जाये। जनपदों के बडे-बडे स्कूलों के द्वारा स्कूल कैंपस में वाहन पार्किंग की व्यवस्था नही दी जाती है, जिस कारण स्कूलों के बाहर सडक पर जाम लगता है व दुर्घटनाए ज्यादा होती है। इस हेतु स्कूलों को परिवहन विभाग की ओर से कडी हिदायत दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें स्कूलों को स्कूल कैंपस में पार्किंग किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा खनन की भारी गाडियों का स्कूल के बच्चों के आने जाने के समय के साथ समयन्वयन स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे स्कूली बच्चों को भारी वाहनों के कारण होने वाली परेशानी व दुर्घटना का सामना न करना पडे। मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक के कम में उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, आर०टी०ओ० व ए०आर०टी०ओ०, पैरेन्ट्स एसोसियेशन को सम्मिलित करते हुये निकट भविष्य में बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे उक्त सम्बन्ध में एक प्रभावी गाईलाईन तैयार की जा सके।

व्यापार की राह पर अमेरिका की नरमी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना महज एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यापार राजनीति का स्पष्ट संकेत है। लंबे समय तक सख्त रुख के लिए पहचाने जाने वाले ट्रंप ने इस कदम के जरिए यह संदेश दिया है कि भारत के साथ टकराव की बजाय अब साझेदारी ज्यादा व्यावहारिक और लाभकारी मानी जा रही है। यह टैरिफ कटौती ऐसे दौर में सामने आई है जब वैश्विक सप्लाई चेन दबाव में है और अमेरिका को भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों की जरूरत है। भारत के लिहाज से यह फैसला निर्यातकों को राहत देने के साथ-साथ निवेश का भरोसा भी मजबूत करता है। कुल मिलाकर, ट्रंप की यह नरमी बताती है कि व्यापार की मेज पर अब सख्ती नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद की जगह बन रही है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने का फैसला भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और बड़े देश अपने-अपने व्यापारिक हितों को नए सिरे से संतुलित करने में जुटे हैं। ट्रंप का यह फैसला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक संदेश भी छिपा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ाकर अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। ट्रंप प्रशासन की पहचान भी इसी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति से जुड़ी रही है, जिसके तहत आयात पर सख्ती और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। लेकिन भारत के मामले में अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। टैरिफ में बड़ी कटौती यह संकेत देती है कि अमेरिका भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार के रूप में देखने लगा है। इस फैसले से सबसे सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर इंजीनियरिंग उत्पाद, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और आईटी से जुड़े उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। पहले ऊंचे टैरिफ के कारण भारतीय उत्पाद महंगे पड़ते थे, जिससे उनकी मांग पर असर पड़ रहा था। अब टैरिफ घटने से लागत कम होगी और भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकेंगी।यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित करने की दिशा में भी एक कदम है। अमेरिका लंबे समय से भारत के साथ व्यापार घाटे का मुद्दा उठाता रहा है, जबकि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार को खोलने और निवेश के अवसर बढ़ाने की बात करता रहा है। टैरिफ में कटौती से यह संकेत मिलता है कि दोनों देश टकराव की बजाय बातचीत और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी ट्रंप का यह कदम अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा, तकनीक, इंडो-पैसिफिक रणनीति और वैश्विक राजनीति में भी दोनों देश एक-दूसरे के करीबी साझेदार बनकर उभरे हैं। ऐसे में व्यापारिक सख्ती रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती थी। टैरिफ में नरमी दिखाकर ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी व्यापारिक मतभेदों से ऊपर है। भारत सरकार की ओर से भी इस फैसले को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते की संभावनाएं मजबूत होंगी। भारत पहले ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों के जरिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की यह नरमी निवेशकों के भरोसे को और मजबूत कर सकती है, जिससे भारत में अमेरिकी निवेश बढ़ने की संभावना है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ट्रंप का यह फैसला पूरी तरह स्थायी रणनीति का हिस्सा है या फिर तत्काल परिस्थितियों का परिणाम, यह आने वाला समय बताएगा। अमेरिकी राजनीति और चुनावी माहौल में व्यापारिक फैसले अक्सर

घरेलू दबावों से भी प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद, मौजूदा कदम को भारत के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिसे सही नीति और कूटनीति के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यह फैसला उस बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसमें देश अब सख्त व्यापारिक दीवारों की बजाय लचीले और व्यावहारिक समझौतों की ओर बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद की दुनिया में सप्लाई चेन का पुनर्गठन, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता ने देशों को यह समझा दिया है कि भरोसेमंद साझेदारों के बिना विकास संभव नहीं है। भारत इस संदर्भ में अमेरिका के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में की गई यह कटौती भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नई ऊर्जा भरने वाली मानी जा रही है। यह फैसला न केवल आर्थिक राहत देता है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह नरमी आगे भी बनी रहती है और क्या दोनों देश इसे एक व्यापक और स्थायी व्यापारिक साझेदारी में बदलने में सफल हो पाते हैं।

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का जताया आभार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। यह जानकारी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर एक पोस्ट के जरिए दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ की आबादी की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इनमें व्यापार समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया। ट्रंप ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जहां हर सप्ताह हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी मित्रता के तहत भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

समान कार्य, समान वेतन

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दर्ज की एक और उपलब्धि

उपनल कर्मियों की वर्षों पुरानी लंबित मांग को सीएम धामी ने पूरा किया

उपनल कर्मियों को दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश जारी होने के साथ ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है।

उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत थे, इस बीच कई सरकारें बदली। आखिरकार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को दस साल की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का शासनादेश जारी हो गया है। यह उपलल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों लोगों के भविष्य से जुड़े एक और जटिल विषय का समाधान कर दिया है।

जिससे ना सिर्फ विभागों की कार्य दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि उपनल कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे वर्षों पुरानी लंबित मांगों पर ठोस कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं।

उपनलकर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन प्रदान कर दिया गया है। सरकार कार्मिक हितों के लिए पहले दिन से ही प्रतिबद्ध है। हम प्रदेश हित में हर जटिल मुद्दे का समाधान निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं।

पुण्यतिथि पर स्मृतियों में गूंजी स्वर कोकिला लता मंगेशकर

6 फरवरी 2022.. वह तारीख जब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का संगीत एक पल के लिए खामोश हो गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इसी दिन अंतिम सांस ली और उनके साथ ही एक युग भौतिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आवाज कभी विदा नहीं हुई। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश के कोने-कोने में वही स्वर फिर से स्मृतियों में गूंज उठे हैं, कहीं रेडियो पर, कहीं मोबाइल की प्लेलिस्ट में, कहीं नम आंखों के बीच। लता मंगेशकर सिर्फ महान गायिका नहीं थीं, वे भारत की सामूहिक भावना की आवाज थीं। उनके गीतों में मां की लोरी थी, प्रेम की कोमलता थी, विरह की टीस थी और देशभक्ति की ऐसी आग थी, जिसने पीढ़ियों को जोड़कर रखा। जब उन्होंने गाया, तो शब्दों को आत्मा मिली और सुरों को अमरता। पुण्यतिथि पर देशवासियों ने उन्हें केवल याद ही नहीं किया, बल्कि उनके स्वर में खुद को फिर से खोजा भी। यही लता मंगेशकर की सबसे बड़ी विरासत है। उनकी आवाज हर पीढ़ी के दर्द, प्रेम और उम्मीद की भाषा बन गई। लता जी भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं रहीं, लेकिन उनका संगीत हमारे जीवन में सांस की तरह रच-बस गया है। उनके गीत आज भी किसी मां की ममता बनकर बहते हैं, किसी प्रेम कहानी की धड़कन बन जाते हैं और किसी उदास मन के लिए सहारा बनते हैं। समय बदला है, दौर बदले हैं, लेकिन लता मंगेशकर का स्वर आज भी उतना ही जीवित, उतना ही प्रासंगिक और उतना ही आत्मीय है, जैसे वह कभी गई ही न हों।

6 फरवरी। यह तारीख हर साल देश के संगीतप्रेमियों के दिल में एक गहरी खामोशी उतार देती है। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ था और उसी दिन भारतीय संगीत ने अपनी सबसे उज्ज्वल, सबसे पवित्र और सबसे भरोसेमंद आवाज को खो दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सिर्फ याद नहीं कर रहा, बल्कि उनके सुरों में खुद को फिर से तलाश रहा है। रेडियो से लेकर मोबाइल फोन तक, मंदिरों से लेकर घरों के आंगन तक, हर जगह वही आवाज गूंजती महसूस होती है जिसने दशकों तक भारत की भावनाओं को स्वर दिया। लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थीं। वे उस भारत की आवाज थीं, जो प्रेम में भी विश्वास करता है, पीड़ा में भी गरिमा रखता है और देशभक्ति में भी विनम्र रहता है। उनके गाए गीत किसी एक दौर या पीढ़ी तक सीमित नहीं रहे। "ऐ मेरे वतन के लोगों" में राष्ट्र का आत्मसम्मान झलका, "लग जा गले" में प्रेम की शुद्धता बहती दिखी और "तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा" में जीवन की अधूरी सच्चाई। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है। लता जी का सफर आसान नहीं था। इंदौर से शुरू हुई उनकी संगीत यात्रा मुंबई की संघर्ष भरी गलियों से होकर विश्व मंच तक पहुंची। उन्होंने हजारों गीत गाए, लेकिन हर गीत में वही सादगी, वही अनुशासन और वही आत्मा बनी रही। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन जब गाया तो पूरी दुनिया ठहर गई। उनकी आवाज में तकनीक से ज्यादा तपस्या थी और सुरों से ज्यादा संवेदना। बुजुर्गों के लिए वे स्मृतियों की साथी हैं, युवाओं के लिए शुद्ध संगीत की पहचान और बच्चों के लिए सुरों की पहली सीढ़ी। शायद यही कारण है कि लता मंगेशकर को याद करते समय आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दिल में एक सुकून भी उतर आता है। वे चली गईं, लेकिन उनका संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए ठहर गया है।

लता मंगेशकर का जाना अंत नहीं निरंतरता है

लता मंगेशकर की पुण्यतिथि अब केवल स्मरण का दिन नहीं रह गई है, यह आत्ममंथन का अवसर भी बन चुकी है। आज के तेज, शोरगुल भरे और डिजिटल संगीत के दौर में जब आवाजों को तकनीक से संवारा जाता है, तब लता जी का स्वर हमें यह याद दिलाता है कि असली ताकत सादगी और साधना में होती है। यही वजह है कि नई पीढ़ी भी आज उनके गीतों की ओर लौट रही है और उन्हें फिर से खोज रही है। कुछ वर्षों में यह साफ देखा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और म्यूजिक ऐप्स पर लता मंगेशकर के गीतों की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। उनकी पुण्यतिथि पर रेडियो चैनलों ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए, संगीत सभाओं में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और देश-विदेश में बसे भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन किया। यह दिखाता है कि लता जी सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि वैश्विक संगीत धरोहर का हिस्सा हैं। संगीत विशेषज्ञों का मानना है कि लता मंगेशकर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने गीत को मनोरंजन से ऊपर उठाकर भावना और संस्कार का माध्यम बनाया। उन्होंने कभी गीत को हल्केपन में नहीं लिया। हर शब्द, हर सुर उनके लिए जिम्मेदारी था। शायद यही वजह है कि उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी राष्ट्रीय आयोजनों में आत्मा को झकझोर देते हैं और उनके गाए भजन आज भी लोगों को भीतर तक छू जाते हैं।

पुण्यतिथि के अवसर पर कई संगीत संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या आज हम उस विरासत को संभाल पा रहे हैं, जो लता मंगेशकर जैसी महान कलाकारों ने छोड़ी है। यह सवाल सिर्फ संगीत का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का भी है। लता जी का संगीत हमें यह सिखाता है कि कला में अनुशासन, विनम्रता और निरंतर साधना कितनी जरूरी है। लता मंगेशकर का जाना एक युग का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी निरंतरता की शुरुआत थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी।

उनके स्वर आज भी सुबह की प्रार्थना में, शाम की तन्हाई में और राष्ट्र के गर्व के क्षणों में गूंजते हैं। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत हमारी सांसों के साथ चलते हैं। शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। जब उसका अस्तित्व समय से बड़ा हो जाए। लता मंगेशकर ने यही किया। उनकी पुण्यतिथि हमें यह याद दिलाती है कि कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होतीं, वे सिर्फ स्मृतियों में और गहरी उतर जाती हैं।

जब लता मंगेशकर की आवाज घर का हिस्सा होती थी

जब लता मंगेशकर की आवाज घर का हिस्सा होती थी एक समय था जब भारत के हर घर में लता मंगेशकर की आवाज किसी सदस्य की तरह मौजूद रहती थी। सुबह रेडियो से आती प्रार्थना हो, दोपहर में बजता कोई फिल्मी गीत या फिर रात को दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम, लता जी का स्वर बिना दस्तक दिए घर में दाखिल हो जाता था। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल में उतर जाती थी। आज जब उनकी पुण्यतिथि आती है, तो यही एहसास सबसे ज्यादा गहराता है कि हमने सिर्फ एक गायिका नहीं खोई, बल्कि अपने जीवन की एक स्थायी ध्वनि खो दी। लता मंगेशकर की खासियत यह नहीं थी कि उन्होंने कितने गीत गाए, बल्कि यह थी कि हर गीत को उन्होंने अपना बना लिया। वे प्रेम गीत गाती थीं तो उसमें शालीनता होती थी, दर्द गाती थीं तो उसमें गरिमा होती थी और देशभक्ति गाती थीं तो उसमें विनम्र गर्व झलकता था। उनकी आवाज कभी आक्रामक नहीं हुई, फिर भी वह सबसे प्रभावशाली रही। शायद यही कारण है कि उनकी आवाज पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी बन गई। आज के दौर में जब संगीत तेजी से बदल रहा है, तब लता जी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। नई पीढ़ी, जिसने उन्हें मंच पर कभी नहीं देखा, आज भी उनके गीत सुनती है। यह सिर्फ नॉस्टेल्जिया नहीं है, बल्कि उस शुद्धता की तलाश है, जो आज के शोर में कहीं खोती जा रही है। उनके गीत सुनते हुए लगता है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऊंची आवाज या भारी संगीत की जरूरत नहीं होती, बस सच्चाई चाहिए। उनकी पुण्यतिथि पर देशभर में होने वाली श्रद्धांजलियां यह साबित करती हैं कि लता मंगेशकर किसी एक भाषा, क्षेत्र या वर्ग की नहीं थीं। वे पूरे देश की आवाज थीं। मराठी से हिंदी, बंगाली से उर्दू तक, हर भाषा में उनका स्वर एक-सा आत्मीय लगता था। उन्होंने भारत की विविधता को सुरों में पिरोया और उसे एक साझा भावनात्मक अनुभव बना दिया। आज जब हम लता जी को याद करते हैं, तो यह एहसास भी होता है कि कुछ कलाकार समय से आगे निकल जाते हैं। वे अपने दौर में नहीं रुकते, बल्कि हर नए दौर में नए अर्थ के साथ लौटते हैं। लता मंगेशकर भी ऐसी ही कलाकार हैं। उनके गीत आज भी बजते हैं, आज भी रुलाते हैं, आज भी सुकून देते हैं, और शायद आने वाली पीढ़ियों को भी देते रहेंगे। लता जी चली गईं, लेकिन उनकी आवाज हमारे जीवन से गई नहीं। वह अब भी किसी अकेले पल में सहारा बन जाती है, किसी खुशी के क्षण में मिठास घोल देती है और किसी राष्ट्रीय अवसर पर गर्व से सीना चौड़ा कर देती है। शायद यही अमरता है। जब इंसान चला जाए, लेकिन उसकी उपस्थिति कभी खत्म न हो।

पुष्कर सिंह धामी के गुड गवर्नेंस को मिली 234 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम की कार्यकुशलता और प्रयासों से आवास विभाग को मिली इस प्रोत्साहन राशि से अब डॉ. आर राजेश कुमार ग्राउंड जीरो पर कुछ नया कर दिखायेंगे। डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने आवास विभाग को संवारने के लिए कई वर्ष दिये हैं। अब उनके नक्शे कदम पर चलकर डॉ. आर राजेश कुमार विकास की नई इबारत लिखेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों का लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए 03 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड और निकायों में स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। आवास विभाग के प्रयास सफल मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अरबन लैंड एंड प्लानिंग रिफार्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किये थे, जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी तरह पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए 05 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलबध कराने के साथ ही शहरों की भीड़ भाड़ को कम करते हुए, उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों मे शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पूरी निष्ठा के साथ अमल में लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए रिफार्म पर 264.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है, इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। उत्तराखंड गुड गर्वनेंस का एक आदर्श मॉडल बनकर सामने आया है।

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू एवं ग्राउंडिंग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

पर्यटन, उद्योग और निवेश के नए अवसरों पर विशेष फोकस

स्पिरिचुअल जोन, आयुर्वेद एम्स और भराड़ीसैंण में मंदिर अवसंरचनात्मक निर्माण को प्राथमिकता में लेने के मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत हुए एमओयू तथा उनकी ग्राउंडिंग (क्रियान्वयन) की प्रगति की समीक्षा हेतु उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए एमओयू की वर्तमान स्थिति, जमीनी प्रगति, अवरोधों तथा आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

एमओयू ग्राउंडिंग में ऐतिहासिक प्रगति, मुख्यमंत्री ने बताया राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि

बैठक में अवगत कराया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत कुल 3,57,693 करोड़ रुपये के 1,779 एमओयू संपादित किए गए थे, जिनमें से अब तक 1,06,953 करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के औद्योगिक एवं आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह राज्य में निवेशकों के विश्वास, बेहतर कानून-व्यवस्था, सुशासन और उद्योग अनुकूल वातावरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक परिणाम को और आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका लाभ राज्यहित में लिया जाना चाहिए।

एमओयू ग्राउंडिंग में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री के स्पष्ट और सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि एमओयू एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर आ रहे अवरोधों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

प्रत्येक संबंधित विभाग में एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो एमओयू ग्राउंडिंग की सतत मॉनिटरिंग करे। यदि किसी नीति में संशोधन, सरलीकरण अथवा शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र पैरवी की जाए।

उद्योगपतियों के साथ नियमित संवाद और संपर्क बढ़ाया जाए तथा उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटलीकरण,सरलीकृत प्रक्रियाएं और उद्योग फ्रेंडली इकोसिस्टम से संबंधित सुधारों की जानकारी दी जाए। निर्देश दिए कि परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में अनावश्यक देरी बिल्कुल न हो, कार्यों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, स्पष्ट टाइमलाइन के अनुसार कार्य पूर्ण हों और किसी भी प्रकार की पेंडेंसी न रखी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ विभागों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने प्रशंसा भी की।

पर्यटन, उद्योग और निवेश के नए अवसरों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जिन क्षेत्रों में होटल निर्माण की व्यापक संभावनाएं हैं- जैसे पिथौरागढ़, कैंची धाम सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों- वहाँ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग स्पेशल टूरिस्ट जोन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एरिया आधारित फोकस पॉलिसी तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योगों को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों में प्रत्येक माह "उद्योग मित्र समिति" की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें उद्योगों से जुड़े मुद्दों का समाधान तथा उद्योग-अनुकूल निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

संस्कृति, अध्यात्म और संतुलित विकास को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और प्राचीन गौरवशाली विरासत का केंद्र बिंदु है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन पर आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आवश्यक होमवर्क करने, हिंदू स्टडीज सेंटर एवं प्राच्य शोध केंद्र से संबंधित पूर्व निर्देशों पर अग्रिम कार्रवाई करने, स्पिरिचुअल जोन डेवलपमेंट, भराड़ीसैंण में मंदिर एवं अन्य रचनात्मक निर्माण कार्य तथा आयुर्वेद एम्स की स्थापना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनय शंकर पांडेय, रणजीत सिन्हा, एस. अदांकी , श्री सी. रवि शंकर, श्री डी. एस. गर्ब्याल, वन विभाग से श्री रंजन कुमार मिश्रा, अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

डीजीपी उत्तराखंड की हाई-लेवल समीक्षा बैठक
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस

पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड श्री दीपम सेठ की अध्यक्षता में आज सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गढ़वाल एवं कुमाऊँ रेंज प्रभारी सहित समस्त जनपदों, STF के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक सम्मिलित हुए। बैठक में वर्तमान अपराध परिदृश्य, कानून व्यवस्था की स्थिति, विवेचनाओं एवं जनशिकायतों के निस्तारण की व्यापक समीक्षा कर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जारी प्रमुख निर्देश

◉ हाल ही में जनपद देहरादून के ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना पर लापरवाही बरतने पर एम्स चौकी प्रभारी एस.आई. साहिल वशिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। साथ ही कोतवाली नगर, देहरादून में युवती के जघन्य हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी एस.आई. प्रद्युम्न नेगी को भी निलम्बित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत दोनों प्रकरणों की जांच एस.पी. क्राइम श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे को सौंपी गयी है। घटना में अन्य कर्मियों द्वारा शिथिलता बरते जाने की 07 दिवस के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

◉ जनपद हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास जयन्ती पर दो पक्षों में हुए संघर्ष

◉ डीजीपी उत्तराखंड की अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई-लेवल समीक्षा बैठक
◉ गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही
◉ लैंड फ्रॉड मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी कार्यवाही के निर्देश, सीओ की प्रारम्भिक होगी अनिवार्य
◉ सिविल मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही
◉ पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति के तहत सतर्कता विभाग करे सख्त कार्यवाही- डीजीपी

एवं गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पर हल्का प्रभारी चुड़ियाला एस.आई. सूरत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम, हरिद्वार श्री जितेन्द्र मेहरा को सौंपी गयी है। साथ ही घटना में अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा लापरवाही बरते जाने की 07 दिवस के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

◉ जनपद ऊधमसिंहनगर के सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण में भूमि सम्बन्धी मामले में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के दृष्टिगत भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) के मामलों में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकारी (सीओ) स्तर पर समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी द्वारा पारदर्शी जांच करते हुए स्पष्ट रूप से सिविल अथवा क्रिमिनल प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा। तदोपरान्त ही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही लम्बित भूमि संबंधी मामलों की पुलिस मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

◉ माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस महानिदेशक द्वारा सतर्कता विभाग से भ्रष्ट आचरण करने वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कहा गया है। बैठक में महानिदेशक, अभिसूचना एवं सुरक्षा- अभिनव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक विजिलेंस, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन ए.पी. अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक, पी/एम- विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र- रिधिम अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार कृष्ण कुमार वी.के., पुलिस महानिरीक्षक, साइबर नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा-करन सिंह नगन्याल, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र सदानन्द दाते, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक- योगेन्द्र रावत, धीरेन्द्र गुंज्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

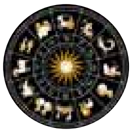
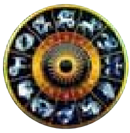

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- आज बच्चों के करियर को लेकर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, और वह सही साबित होगा। किसी बुजुर्ग की मदद से पैसे मिलने की उम्मीद पूरी हो सकती है। सरकारी नौकरी वालों को मनचाही जगह जिम्मेदारी मिल सकती है। छाती से जुड़ी परेशानी, नजला-जुकाम हो सकता है। आयुर्वेद अपनाना फायदेमंद रहेगा। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 5

वृषभ राशि- काम के प्रति आपकी काबिलियत साफ नजर आएगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। आपका अच्छा रवैया हर काम में सफलता दिलाएगा। भागदौड़ और खर्च बढ़े रहेंगे। घबराएं नहीं, हल मिल जाएगा। काम निकलवाने में समझदारी रखें। ज्यादा सोचने में समय खराब न करें। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 2

मिथुन राशि- चुनौतियों का हल आसानी से निकाल लेंगे। पिछले समय की मेहनत का अचानक फायदा मिल सकता है। युवाओं को भविष्य का रास्ता समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों से बात करके अच्छा लगेगा। मीडिया, मार्केटिंग और प्रचार से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। लव- घर में सुख-शांति रहेगी। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 5

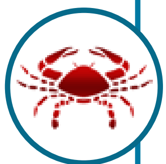

कर्क राशि- योजनाओं को लागू करने का सही समय है। घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। युवा भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, पर हल जल्दी मिलेगा। अभी विस्तार की योजना टालें। पैसों को लेकर दबाव रह सकता है। पति-पत्नी के रिश्ते मधुर रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 8

सिंह राशि- युवाओं को पढ़ाई और प्रतियोगिता में सही सलाह मिलेगी। घर में ज्यादा रोक-टोक न करें। पड़ोसी से बहस हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें। लेन-देन में सावधानी रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे। डील करते समय जल्दबाजी न करें। धैर्य रखना जरूरी है। युवाओं को करियर के तेज मुकाबले में अधिक मेहनत करनी होगी। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 2

कन्या राशि- सामाजिक संपर्क से लाभ मिल सकता है। घर की मरम्मत या बदलाव की योजना शुरू करने का अच्छा समय है। परिवार में ज्यादा रोक-टोक न करें। व्यवहार में नरमी रखें। युवाओं को मनचाहा परिणाम पाने के लिए और मेहनत करनी होगी। साथ काम करने वालों से संबंध अच्छे रखें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 3

तुला राशि- चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करें। रचनात्मक और धार्मिक कामों में मन लगेगा। दूसरी गतिविधियों में व्यस्तता से निजी काम टल सकते हैं। लापरवाही न करें। चिड़चिड़ापन और गुस्सा लक्ष्य से भटका सकता है। कारोबार की बात बाहरी लोगों से साझा न करें। गिरने या चोट लगने का योग है। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 1

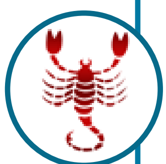

वृश्चिक राशि- अपने लोगों से मुलाकात होने से मन खुश रहेगा। रुका काम पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी डील के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। छोटी-छोटी बातों में दिक्कत आएगी। बिजनेस पार्टनर और कर्मचारियों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। ठंड और प्रदूषण से बचें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

धनु राशि- अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें, सफलता मिलेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े काम में अच्छा नतीजा मिल सकता है। किसी सम्मानित व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। घर-परिवार में सक्रिय रहें। हल्की नोकझोंक हो सकती है। किसी रिश्तेदार की खबर से मन विचलित हो सकता है। अपनी योजना गुप्त रखें। भाग्यशाली रंग- आरेंज, भाग्यशाली अंक- 7

मकर राशि- पुश्तैनी संपत्ति का विवाद किसी के बीच-बचाव से सुलझ सकता है। विद्यार्थी अच्छे कॉलेज में दाखिले में सफल हो सकते हैं। समय का सही उपयोग करें। काम करने का तरीका दोबारा जांचें। मेहनत ज्यादा और लाभ कम दिखेगा, पर यही मेहनत आगे अच्छा फल देगी। घर में सुख-शांति और प्रेम बना रहेगा। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 6

कुंभ राशि- घर के मुद्दों पर आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी। घर में सुधार करते समय वास्तु के नियम मानना फायदेमंद रहेगा। अपनी कमियां पहचान कर सुधार करें। उबाऊ दिनचर्या से बाहर निकलने के लिए मित्रों और रिश्तेदारों को समय दें। नौकरी वाले काम समय पर पूरा करें। शादी के बाहर के संबंधों से दूर रहें। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 4

मीन राशि- आप जिस भी काम को करेंगे, उसमें मनचाही सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जमीन या संपत्ति से जुड़ा अटका काम किसी की मदद से सुलझ सकता है। पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें या आज टाल दें। जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें। प्रेम संबंध और गहरे होंगे। ज्यादा व्यस्तता से तनाव बढ़ सकता है। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 5

अम्मा का खौफ: मर्दानी 3 की नई पहचान

मर्दानी 3 में पहली महिला विलेन 'अम्मा' के रूप में मल्लिका प्रसाद ने दर्शकों को प्रभावित किया है। यश राज फिल्म ने उनके किरदार को रिलीज से पहले गुप्त रखा ताकि सरप्राइज बना रहे। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हिट फिल्म मर्दानी फ्रैंचाइजी की नई फिल्म मर्दानी 3 में पहली बार एक महिला विलेन का किरदार सामने आया है। अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद द्वारा निभाया गया 'अम्मा' का रोल अपनी रहस्यमयी और डर पैदा करने वाली मौजूदगी के कारण दर्शकों के बीच खास चर्चा का विषय बन गया है। मल्लिका प्रसाद ने खुलासा किया है कि फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें पूरी तरह पर्दे में रखने के लिए यश राज फिल्म्स ने खास रणनीति बनाई थी, ताकि बड़े पर्दे पर उनके किरदार का असर और ज्यादा मजबूत दिखे।

रिलीज से पहले क्यों छिपाया गया 'अम्मा' का किरदार मल्लिका बताती हैं कि फिल्मों में सरप्राइज फैक्टर हमेशा खास होता है। मर्दानी सीरीज अपने मजबूत विलेन के लिए जानी जाती है, इसलिए इस बार भी 'अम्मा' के किरदार को आखिरी समय तक गुप्त रखा गया। मेकर्स का मानना था कि अगर प्रमोशन के दौरान किरदार की झलक दिखा दी जाती, तो दर्शकों पर उसका प्रभाव कम हो सकता था। इसलिए उन्होंने मल्लिका को रिलीज के बाद ही मीडिया और प्रमोशन में सामने लाने का फैसला किया।

सोशल मीडिया पर 'अम्मा' के अभिनय की तारीफ फिल्म के ट्रेलर और रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है। सोशल मीडिया पर मल्लिका प्रसाद के अभिनय को लेकर लोगों ने खूब सराहना की है। उनके अनुसार, दर्शकों से मिल रहा प्यार यह दिखाता है कि 'अम्मा' का किरदार अलग और प्रभावशाली साबित हुआ है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और गानों ने भी इस किरदार के डर और प्रभाव को और मजबूत बनाया है। मल्लिका ने बताया कि जॉन स्टुअर्ट एडुरी का बैकग्राउंड स्कोर और सार्थक कल्याणी के गाने 'अम्मा' के किरदार को अलग पहचान देते हैं। खास तौर पर 'ईविल बॉस म्यूजिक' ने किरदार की खौफनाक छवि को और प्रभावी बनाया है। उनका मानना है कि यह किरदार समाज की उस सच्चाई को भी दिखाता है, जहां अन्याय और शोषण से अपराध पैदा होते हैं। मर्दानी 3 हिट बनने की ओर रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मजबूत कलेक्शन, सकारात्मक समीक्षाएं और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के चलते फिल्म के हिट होने की संभावना बढ़ गई है। यह फिल्म मर्दानी फ्रैंचाइजी को लगातार तीसरी हिट देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अभिराज मीनावाला के निर्देशन और आदित्य चोपड़ा के निर्माण में बनी यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित दमदार कहानी को आगे बढ़ाती है। मर्दानी सीरीज आज भारतीय सिनेमा की सफल महिला-प्रधान फ्रैंचाइजी के रूप में जानी जाती है। यह देश की इकलौती ऐसी हिट फिल्म सीरीज है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी केंद्र में हैं।

मर्दानी 3 की रिलीज का एक खास पहलू यह भी है कि यह फिल्म रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल पूरे होने के मौके पर आई है। यह उपलब्धि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी खास रही, जहां उनकी शानदार विरासत का जश्न मनाया गया।

Rishikesh HANDMADE
soulful handmade creations

PREMIUM AUTHENTIC PRODUCTS OF
HIMALYAN FIBRE

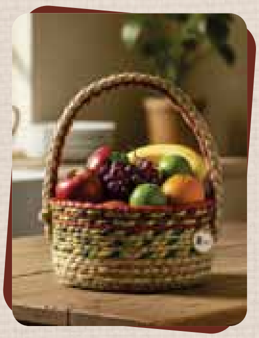

Rishikesh
Natural Fiber Handicrafts Producer Company Pvt. Ltd.

Visit for Products: ***www.rishikeshhandmade.com***

MOTHER CONCERN
BHARTIYA GRAMOTTHAN SANSTHA

Gramotthan Bhawan:
Upper Road Dhalwala (Rishikesh)
Tehri Garhwal, Uttrakhand 249201
Email: *bgsuttranchal@rediffmail.com*
Contact: *(+91) 7351009107, 9411571947*
Website: *https://bgsuttarakhand.org.in/*

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027